अमर उजाला

छह दिन में उद्योगों को होगा करोड़ों का नुकसान

गत्ता उत्पादन ठप होने से 80 फीसदी उद्योग होंगे प्रभावित, 30 हजार टन तैयार माल की कमी होगी

● अनिमेष कौशल

बद्दी (सोलन)। गत्ता उद्योगों की आठ मार्च से प्रस्तावित हड़ताल से प्रदेश के अस्सी फीसदी उद्योग प्रभावित होंगे। पैकिंग के लिए पूरी तरह से गत्ता-पेटी पर निर्भर उक्त उद्योगों को हड़ताल से करीबन पचास करोड़ का नुकसान उठाना पड़ेगा। उधर, कच्चे माल को तैयार करने वाले पेपर मिल मालिकों द्वारा बढ़ी हुई कीमतों पर ही अपना सामान बेचने के निर्णय ने गत्ता उद्योगों की मुश्किलों को और अधिक बढ़ा दिया है।

प्रदेश गत्ता-पेटी निर्माता उद्योग संघ ने आठ मार्च से 13 मार्च तक प्रदेश के गत्ता उद्योगों को पूर्ण रूप से बंद रखने के फरमान ने अन्य उद्योगों में हड़कंप मचा दिया है। विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में पैकिंग करने के लिए गत्ते पर निर्भर नब्बे फीसदी उद्योगों को मार्च माह के पहले सप्ताह में गत्ते की पेटियां न मिलने की चिंता अभी से सताने लग पड़ी है। जबकि, ऐसी ही स्थिति औद्योगिक क्षेत्र सोलन, परवाणू, कालाअंब, मेहतपुर, संसारपुर टैरस, ऊना व टाहलीवाल सहित अन्य क्षेत्रों में भी उत्पन्न हो गई है।

बद्दी में बैठक को संबोधित करते गत्ता-पेटी निर्माता उद्योग संघ के पदाधिकारी।

गत्ता-पेटी निर्माता उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र सहगल व बीबीएन गत्ता-पेटी उद्योग संघ के महासचिव सुरेन्द्र जैन का कहना है कि कच्चे माल की बढ़ी हुई कीमतों के चलते हालात ऐसे हो गए है कि गत्ता निर्माताओं को अपना खर्चा तक निकालना मुश्किल हो गया है। बढ़ी हुई कीमतों के हिसाब से अन्य उद्योग गत्ता पेटी खरीदने में आनाकानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छह दिनों की हड़ताल के दौरान तीस हजार टन तैयार माल की कमी होगी। इसके चलते गत्ता उद्योगों के साथ-साथ अन्य उद्योग भी प्रभावित होंगे।

इस बाबत बीबीएन उद्योग संघ के सचिव अरुण रावत का कहना है कि गत्ता उद्योगों की हड़ताल से क्षेत्र के सभी उद्योगों में कामकाज प्रभावित होगा। उद्योगों को करोड़ों का नुकसान होने की संभावना है।

दो पेपर मिलों को किया ब्लैक लिस्ट

उत्तर भारत के गत्ता-पेटी उत्पादकों ने दो पेपर मिलों का सामाजिक बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बीते दिन आयोजित बैठक में एक बद्दी और एक दिल्ली की मिल से भविष्य में किसी भी प्रकार का लेनदेन न करने पर सहमति जताई गई है। पंजाब पैकेजिंग उद्योग संघ के अध्यक्ष आरपी सिंह, हिमाचल पैकेजिंग उद्योग संघ के अध्यक्ष देवेन्द्र सहगल व उत्तर भारत के पैकेजिंग उद्योगों की संयुक्त कार्यकारी समिति के संयोजक हरीश मदान ने बताया कि उक्त दोनों पेपर मिलों के मालिकों का गत्ता उत्पादकों के प्रति रवैया ठीक नहीं है। सभी उद्योगपतियों ने एकमत होकर दोनों पेपर मिलों को ब्लैक लिस्ट किया है।

सेब उत्पादकों को महंगी मिलेगी गत्ते की पेटी

बद्दी (सोलन)। प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले सेब उत्पादकों को भी कच्चे माल में हुई वृद्धि का सामना करना पडेगा। पहले 28 रुपए की कीमत में मिलने वाली गत्ते की पेटी सेब सीजन के दौरान 38 से 40 रुपए तक पहुंच जाएगी। इसके चलते पहले से ही मौसम की बेरुखी का सामना कर रहे प्रदेश के बागवानों को दोहरी मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं। गत्ता-पेटी उद्योग संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिवेन्द्र सहगल ने बताया कि सेब उत्पादकों को इस बार मंहगे दामों पर पेटियां लेनी पड़ेंगी।

आठ मार्च से छह दिन हड़ताल करेंगे गत्ता उद्योग

● अमर उजाला ब्यूरो

बद्दी (सोलन)। उत्तर भारत की पेपर मिलों के विरोध में 8 से 13 मार्च तक हिमाचल और पंजाब के गत्ता उद्योग हड़ताल पर रहेंगे। गत्ता उद्योग संघ की संयुक्त कार्यकारी समिति के आह्वान पर बद्दी में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। उधर, तीन मार्च को नई दिल्ली के जंतर-मंतर में आयोजित होने वाले विरोध-प्रदर्शन के बाद उत्तर भारत के अन्य राज्य भी इस हड़ताल में शामिल हो सकते हैं। बैठक में पंजाब पैकेजिंग उद्योग संघ के अध्यक्ष आरपी सिंह व हिमाचल पैकेजिंग उद्योग संघ के अध्यक्ष देवेंद्र सहगल ने छह दिन उत्पादन ठप रखने का निर्णय लिया है। बैठक में पक्ष रखा गया कि उत्तर भारत की पेपर मिलों ने 25 जनवरी को एक रुपया प्रति किलो, तीन जनवरी को दो रुपया प्रति किलो तथा 12 फरवरी को फिर एक रुपया प्रति किलो कच्चे माल की कीमतें बढ़ाई हैं। आरोप लगाया कि एक्ट का उल्लंघन करते हुए पेपर मिल मालिकों ने एक माह के भीतर तीन हजार से चार हजार रुपए प्रति टन कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि कर दी है। बैठक में संयुक्त कार्यकारी समिति के संयोजक हरीश मदान, उत्तर प्रदेश पैकेजिंग उद्योग संघ के अध्यक्ष शशिधरन, राजस्थान पैकेजिंग उद्योग संघ के अध्यक्ष प्रेम खत्री व उत्तर भारत पैकेजिंग उद्योग संघ के अध्यक्ष राजकमल जिंदल ने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शन के बाद भी पेपर मिलों पर लगाम नहीं कसी तो अन्य उद्योग भी हड़ताल पर जाने को विवश होंगे।

आक्रोश

संयुक्त कार्यकारी समिति के आह्वान पर लिया फैसला